देवभूमि बनी जमीन घोटालों की मंडी

राजेन्द्र जोशी

गुजरात में अडानी बंधुओं को एक रुपये की दर से सरकारी जमीन देने का मामला हो या फिर राजस्थान में रावर्ट वाड्रा की जमीनों की खरीद–फरोख्त। दोनों की मामले लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में गूंजे। भले ही ये मामले देशभर में चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन इस देवभूमि में हो रहे जमीनों के घोटालों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आलम यह है कि यह देवभूमि जमीन घोटालों की मंडी सा बनता जा रहा है। कांग्रेस हो या फिर भाजपा दोनों ही राज्य में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाते रहे हैं। लेकिन विपक्षी दल के रूप में दोनों ही दलों की भूमिका इन घोटालों पर महज विरोध की रस्म अदायगी तक ही सीमित रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमाम में सब नंगे हैं। इसी का नतीजा है कि अरबों की सरकारी जमीन को कौडियों में लुटाने का यह सिलसिला उत्तराखंड में थमता नहीं दिख रहा है।

देहरादून। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने ऐसे ही एक मामले का आरटीआई के जरिए खुलासा किया। सरकार के स्तर पर कोई सुनवाई होने की संभावना न के बराबर ही देख इस मामले में जनहित याचिका के जरिए उत्तराखंड हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

अगल राज्य बनने के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला। कांग्रेस ने राज्य को नई दिशा देने के लिए अपने कद्दावर नेता और विकास पुरुष के रूप में पहचान रखने वाले नारायण दत्त तिवारी को सरकार का मुखिया बनाया। एनडी ने राज्य में औद्योगिकीकरण की दिशा में काम किया। इस बीच केंद्र की तत्कालीन अटल सरकार ने उत्तराखंड को खास औद्योगिक पैकेज भी दे दिया। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए सिडकुल नामक सरकारी संस्था का गठन किया। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपदों में उद्योगों के लिए जमीन का अधिग्रहण करके सिडकुल को दे दिया गया। ऊधमसिंह नगर जिले में तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की खेती जमीन ली गई। इसके लिए महज 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से विवि को भुगतान किया गया। दूसरी तरह हरिद्वार

□अरबों की जमीन चहेतों को कौड़ियों के दाम
□एनडी ने राज्य में औद्योगिकीकरण की दिशा में किया था काम

में बीएचईएल (भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड) की जमीन का तो मुफ्त में ही अधिग्रहण कर लिया। ये जमीन सिडकुल को मुफ्त में ही दे दी गईं। इसके साथ ही सिडकुल नामक यह संस्था नेताओं और अफसरों के गठजोड़ से लिए मोटी कमाई का जरिया सा बन गई है। उद्योगों के लिए मुफ्त में ली गईं इन जमीनों को बड़े बिल्डर्स को आवासीय कालोनी के लिए बेचा जा रहा है। यह सिलसिला अब तक बदस्तूर जारी है। उस वक्त की बची जमीन को बेचा जा रहा तो नई जमीनों का अधिग्रहण भी किया जा रहा है।

उद्योगपतियों को जमीन देने में तमाम तरह के खेल किए जा रहे हैं। कहीं जमीन का लैंड यूज बदले बिना ही बेची जा रही है तो कहीं मिलीभगत करके अरबों की जमीन को कौड़ियों के मोल बेचा जा रहा है। अफसरों, नेताओं और उद्योगपतियों के इस गठजोड़ का सीधा नुकसान राजस्व का हो रहा है। जिस जमीन को बेचकर उद्योगपति अरबों कमा रहा है, उसी जमीन के एवज में राज्य सरकार को राजस्व के रूप में चंद करोड़ रुपये ही मिल रहे हैं। ताजा मामला हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में दो बड़े बिल्डरों को औद्योगिक क्षेत्र में ही आवासीय कालोनी के लिए जमीन बेचने का सामने आया है।

यह मामला सीधे तौर पर रियल स्टेट कारोबार से जुड़ी बड़ी कंपनी सुपरटेक और अंतरिक्ष बिल्डर्स से जुड़ा है। 2012 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद इस खेल का तानाबाना बुना गया। सिडकुल उस वक्त हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के पंतनगर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय कालोनी के जमीन बेचने की शुरुआत की। इसके साथ ही शुरू किया गया सेटिंग और गेटिंग का खेल। यह खेल जब अंजाम तक पहुंचा तो नतीजे के रूप में सुपरटेक कंपनी के हिस्से में पंतनगर में 23 एकड़ और अंतरिक्ष के हिस्से में भी 23 एकड़ जमीन हरिद्वार में (पेंटागन माल के पास) आई। यह कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। इससे पहले देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के सिडकुल (औद्योगिक आस्थान) मामले सामने आते रहे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस मनमानी पर अंकुष कौन लगाएगा और क्या इस तरह के घोटालेबाज सरकार में इसी तरह से अपना दबदबा बनाए रखेंगे।

ऐसे किया गया खेल

आरटीआई के तहत सिडकुल से मिले कागजात साफ इषारा कर रहे हैं कि सब कुछ मिली भगत से ही किया गया है। जमीन बेचने के लिए सिडकुल ने 2012 में टेंडर मांगे। इस पर सुपरटेक और अंतरिक्ष कंपनी के अलावा दो गुमनाम सी कंपनियों ने टेंडर डाले। हरिद्वार की जमीन के लिए भी इन्हीं चार कंपनियों के टेंडर आए। टेंडर के साथ अरनेस्ट मनी यानि धरोहर राषि भी जमा करनी थी। यहीं से षुरू हुआ बड़ा खेल। इस जमीन के लिए केवल अंतरिक्ष कंपनी ने ही अरनेस्ट मनी जमा की। बाकी तीन कंपनियों ने यह राषि जमा नहीं की। ऐसे में बोली लगाने के लिए एक मात्र अंतरिक्ष कंपनी ही अधिकृत थी। लिहाजा सिडकुल ने अंतरिक्ष द्वारा लगाई गई कीमत 65 सौ रुपये प्रति वर्ग फुट पर जमीन बेच दी। नियमानुसार बोली लगाने के लिए कम से कम तीन कंपनियों का होना जरूरी था। लेकिन सिडकुल ने इस नियम को दरकिनार करके जमीन अंतरिक्ष बिल्डर्स के नाम कर दी। ऐसे ही खेल पंतनगर की जमीन पर भी किया गया। अंतरिक्ष समेत तीन ने अरनेस्ट मनी जमा नहीं की। जमीन को केवल सुपरटेक ने ही धरोहर राशि टेंडर के साथ जमा की थी। वैध निविदादाता सुपरटेक को मुंहमांगी कीमत 58 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जमीन बेच दी गई।

तीन अरब का एक यह भी घोटाला

हरिद्वार सिडकुल में हीरो मोटो कार्प का घोटाला भी खासा चर्चित हो रहा है। इस कंपनी ने 2006 में अपनी फैक्टरी लगाने के लिए सिडकुल से 214 एकड़ जमीन का सौदा किया। एमओयू होने के बाद कंपनी से अपनी फैक्टरी लगाई और उत्पादन शुरू कर दिया। लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। कंपनी सात साल तक उत्पादन करती रही। रजिस्ट्री के लिए न तो कंपनी ने रुचि दिखाई और न ही सरकारी तंत्र ने इस अनियमितता की ओर कोई ध्यान दिया। घोटालेबाजों की नजर इस मामले की ओर फरवरी–2014 में गई। कंपनी पर रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया गया। फिर एक सौदे के तहत खेल किया गया। 2006 में इस जमीन की कीमत एक हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। उस वक्त नौ फीसदी की दर से स्टांप शुल्क अदा करना होता था। रजिस्ट्री के वक्त जमीन की सरकारी कीमत 3812 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो चुकी थी और स्टांप शुल्क घटकर पांच फीसदी हो गया था। बस यहीं से शुरू हुआ खेल। रजिस्ट्री के लिए जमीन की कीमत तो 2006 वाली ही तय की गई। लेकिन स्टांप शुल्क के लिए 2014 की दरों का इस्तेमाल किया गया। इससे सरकार को राजस्व का दोतरफा नुकसान हुआ है। सूत्रों की मानें तो यह घोटाला तीन अरब रुपये के आसपास का है। मामला मीडिया में छाया तो हरिद्वार के डीएम ने हीरो मोटो कार्प से 22.86 लाख रुपये स्टांप शुल्क में चोरी के साथ ही 88.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यानि इस कंपनी से लगभग 111 करोड़ की वसूली की जानी है। इसके अलावा जमीन के सर्किल रेट के आधार पर सरकार को ढाई अरब यानि 250 करोड़ का चूना अलग से लग रहा है। बताया जा रहा है कि

घोटालेबाज अब इस मामले को भी फाइलों में ही दबाने की कोशिश में जुट गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस कंपनी से 111 करोड़ के साथ ही 250 करोड़ रुपये वसूलने में कामयाब होती है या फिर दूसरे मामलों की तरह ही इसे भी फाइलों में ही कैद कर दिया जाने वाला है।

Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

करोड़ लगाए, अरबों में कमाई

बिल्डरों से सिडकुल की जमीन करोड़ों में खरीदी है और अब अरबों कमा रहे हैं। अंतरिक्ष में हरिद्वार में 66 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगभग 93.800 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। इसके ऐवज में सिडकुल को लगभग 55.30 करोड़ रुपया दिया गया है। अब अंतरिक्ष इस जमीन को 28 से तीस हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच रहा है। अगर कीमत 28 हजार ही मान ली जाए तो अंतरिक्ष को इस जमीन की बिक्री से लगभग 2.60 अरब रुपये की कमाई होगी। मतलब लगभग दो अरब रुपये से ज्यादा का सीधा मुनाफा। इसी तरह सुपरटेक ने पंतनगर सिडकुल में 59 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगभग 96.190 वर्ग मीटर जमीन महज 55.80 करोड़ रुपये में सिडकुल से खरीदी है। इस जमीन का बाजार रेट इस समय 32 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर है। इस लिहाज से इस जमीन की बिक्री से सुपरटेक को लगभग तीन अरब रुपये की कमाई होगी।

कम कर दी सरकारी कीमत

जमीन की इस बिक्री में करोड़ों की हेराफेरी का अनुमान है। सिडकुल ने हरिद्वार की इस जमीन का बेस प्राइस (न्यूनतम कीमत) 5500 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया और बाद में 65 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया। इतना ही नहीं, सौदा पक्का होने के बाद महज एक आदेष करके अंतरिक्ष से 66 सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पैसा देने को कहा गया। अहम बात यह है कि इससे पहले यह सिडकुल सुपरटेक कंपनी को 2007 में इसी जगह पर जमीन 20.556 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से बेच चुका है।

जाति व्यवस्था खत्म करने को अभियान

देहरादून। जाति व्यवस्था को समाप्त करने को लेकर भारत यात्रा से जुड़े के.के. शराचन्द्र द्वारा देश भर में अभियान चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के तहत दून में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान के.के [redacted] कि [redacted]वस्था को खत्म [redacted]भियान को दिन [redacted]र रहे है। इसके [redacted]कार को अनिवार्य [redacted]या गया, जिसमें [redacted]त तक देश से [redacted]ा का खत्म करने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अपनी यात्रा के दौरान वे लोगों को अपने द्वारा लिखित पुस्तक निःशुल्क वितरित करेंगे। उनका कहना था कि पुस्तक में भारत सरकार से 31 दिसंबर 2014 से पहले जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिये संवैधानिक सुधार करने की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया कि यात्रा में सभी राज्यों की राजधानी शामिल होगे और 35 से अधिक शहरों में बैठकें आयोजित की जाएंगी।

[redacted]से की मुलाकात

[redacted]न निवासियों ने एमएनए हरक सिंह रावत से [redacted]ात्र सुलभ शौचालय के जीर्णोद्धार व सड़क और [redacted] अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इस मौके पर [redacted]ों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। [redacted]र्यक्रम के तहत बुधवार को जाखन निवासी स्थानीय [redacted] के नेतृत्व में नगर निगम में एकत्र हुए, जहां उन्होंने [redacted] लेकर एमएनए से मुलाकात की।

निशक्तजनों की कानूनी अभिभावक बनेगी सरकार

मुख्य सचिव निशक्तजनों की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

देहरादून। राज्य सरकार गम्भीर रूप से निःशक्त जनों की कानूनी अभिभावक बनेगी। इसके तहत चार तरह की निःशक्तता आयेगी–सेवेरल पैलेसी, मेंटल रिटार्डिशन, मल्टिपल डिसएबिलिटी और आटिज्म। प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसी तरह जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है।

मुख्य सचिव सुभाष कुमार बुधवार को सचिवालय में भारत सरकार के सामाजिक न्याय

□बीपीएल परिवारों को 8 लाख रूपये और एपीएल के लिए एक करोड रूपये एकमुश्त देगा

मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल ट्रस्ट के बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। नेशनल ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत सरकार के संयुक्त सचिव अजय लाल ने बताया कि उत्तराखंड में रैफल को स्टेट नोडल एजेंसी सेंटर (स्नैक) बनाया गया है। जिलों में गठित समिति में जिलाधिकारियों के अलावा एक स्वयंसेवी संस्था और निःशक्त व्यक्ति होगा। निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वयं सेवी संस्था अपने जनपद में गम्भीर रूप से निःशक्त जनों की पहचान करेगी। स्वास्थ विभाग 18 वर्ष पूर्ण कर चुके इस तरह के निःशक्त लोगों को प्रमाण पत्र देगा। राज्य सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण, रोजगार और लीगल गार्जियनशिप प्रदान करेगी।

मुख्य सचिव ने वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपनी मासिक बैठक में एजेंडा के रूप में इस योजना को भी शामिल कर नियमित रूप से समीक्षा करें। केरल में कोल्लम जनपद के जिलाधिकारी प्रणव ज्योतिनाथ ने अपने राज्य में किये गये सफल प्रयोगों के बारे में जानकारी दी।

इस तरह के लोगों के जो परिवार विघटित हो गये है, उनके लिए 'घरौंदा योजना' है। इसमें 25 एपीएल और 5 बीपीएल परिवारों का एक आवासीय सुविधाओं से युक्त भवन बनाया जायेगा। ट्रस्ट बीपीएल परिवारों को 8 लाख रूपये और एपीएल के लिए एक करोड रूपये एकमुश्त देगा।

सुपरफास्ट खबरें

17 को होगी एमबीए प्रवेश परीक्षा

देहरादून। उत्तराखंड मुक्त विवि द्वारा आयोजित की जाने वाली एमबीए प्रवेश परीक्षा अब 17 अगस्त को होगी। उत्तराखंड मुक्त विवि श्री गुरूराम राय पीजी कालेज देहरादून के क्षेत्रीय निदेशक डा. संदीप नेगी ने बताया कि विवि द्वारा आयोजित की जाने वाली एमबीए प्रवेश परीक्षा, जो 20 जुलाई को आयोजित की जानी थी, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण स्थगित कर दी गयी थी, अब आगामी 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक छात्र, जो प्रवेश फार्म जमा कराने से रह गये थे, आगामी 14 अगस्त तक अपने फार्म को जमा करा सकते है।

अनिश्चित कालीन धरना शुरू

देहरादून, आजखबर। अपनी पांच सूत्रीय मांगो को लेकर उत्तराखण्ड पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षक सोसाइटी ने बुधवार से जोरदार नारेबाजी के बीच अनिश्चित कालीन धरना शुरू कर दिया।

इस अवसर पर आयोजित सभा में सोसाईटी अध्यक्ष सर्वेश चौधरी ने कहा कि संस्था अपनी पांच सूत्रीय मांगो से समय – समय पर सरकार व शासन को अवगत कराते आ रहे है, लेकिन अभी तक उन मांगों के समाधान को किसी प्रकार का भी सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया है, जिससे सोसाइटी सदस्यों में गहरा रोष व्याप्त हो रखा है। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि सरकार व शासन के उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते ही संस्था सदस्यों को आंदोलन शुरू करना पड़ा है। उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर खगेन्द्र अवस्थी, महेन्द्रपाल, सर्वेश चौधरी, सुमित, श्वेता, पूनम रावत, दिव्या नेगी, शीतल, महेश आदि मौजूद थे।

[redacted] बाद भी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं

[redacted]न के नेताओं व [redacted]हो रहे हमलों के [redacted]भारतीय विद्यार्थी [redacted]सपी को ज्ञापन [redacted] चेतावनी दी कि [redacted]हमलों में कोई [redacted]ी तो पुलिस के [redacted] किया जाएगा। [redacted]राष्ट्रीय महामंत्री [redacted]दाधिकारियों व [redacted]एसपी को ज्ञापन [redacted]ना था कि विगत [redacted]वी पीजी कॉलेज [redacted]ाव से ऐन पहले [redacted] के नेताओं व [redacted]रा अभाविप के [redacted]र्ताओं पर हमले [redacted]जाते हैं। पिछले [redacted]न पर जानलेवा

□एसएसपी से मिले एबीवीपी कार्यकर्ता

हमले किये जा रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। 21 जुलाई को भी एनएसयूआई के 20–25 कार्यकर्ताओं ने अभाविप कार्यकर्ता राहुल राय पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में राहुल को गंभीर चोटें आने से 70 टांके लगाने की नौबत पडी। जिनमें से 40 टांके सिर पर ही हैं। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के 36 घंटे बाद भी हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। एबीवीपी का कहना था कि इससे पहले भी संगठन के दो कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वर्ष 2012–13 में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आईएमए गेट के सामने अभाविप के कार्यकर्ताओं पर गोली चलायी थी जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गये थे लेकिन पुलिस ने राज्य सरकार के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की। एनएसयूआई कार्यकर्ता गुण्डागर्दी पर उतारू हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है या फिर हल्की धाराओं में मुकदमे दर्ज किये जाते हैं। यदि पुलिस का अभी भी यही रवैया रहा तो अभाविप पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेगी।

आपदा में जनहानि की केंद्रीय एजेंसी करें उच्च स्तरीय जांच

देहरादून। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद हरिद्वार डा रमेश पोखरियाल निशंक ने संसद में शून्यकाल के दौरान उत्तराखंड में आपदा के बाद उपजे हालातों को उठाते हुए कहा कि केन्द्र द्वारा राज्य को दी गयी राशि का सदुपयोग नही हो पा रहा है सामाजिक,सामरिक,सांस्कृतिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षति को देखते हुए आपदा पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। इसके अलावा यात्रा मार्गों को भी केन्द्र सरकार अपने हाथों में लें और जन हानि प्रकरण की केन्द्रीय एजेंसी से उच्च

स्तरीय जांच करायी जाए। डा निशंक ने कहा कि उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री,गंगोत्री,केदारनाथ बद्रीनाथ,हेमकुंड व कैलाश मानसरोवर यात्रा पर देश और दुनिया के हजारों लोग प्रतिवर्ष आते है; विगत वर्ष केदारनाथ की भीषण त्रासदी ने पूरे देश

□देश के 24 राज्यों के लगभग 20 हजार से अधिक लोगों को जान गंवानी पड़ी थी

को हिलाकर रख दिया था और इसमें देश के 24 राज्यों के लगभग 20 हजार से अधिक लोगों को जान गंवानी पडी थी। जो लोग इस प्रलय से किसी तरह जान बचाकर पहाडों में ऊपर की ओर भागे थे समय पर न निकाले जाने के कारण भूख,प्यास और कडकती ठंड से बेमौत मारे गये। सैकडों कंकाल आज भी जंगलों में मिल रहे हैं और यह उत्तराखंड सरकार की घोर अव्यवस्था तथा संवेदनहीनता का पुख्ता प्रमाण है। राज्य सरकार की घोर चूके कारण कई परिवारों में तो एक व्यक्ति भी जिंदा नही रहा। सडक मार्ग आज तक भी ठीक नही हो पाये और केदारनाथ का पैदल मार्ग तो आज तक भी व्यवस्थित नहीहै। लोग दर–दर भटक रहे हैं और जो लोग जीवित हैं इस अव्यवस्था में भूखों मरने की कगार पर हैं। सीएम, मंत्री तथा प्रशासनिक अधिकारियों के विरोधाभाषी बयानों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है।

केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता राशि का भी सदुपयोग नही हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जो लापरवाही बरती गयी और इससे जो जन हानि हुई है इसकी केन्द्रीय एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच करायी जाए तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।